इजाजत दे दी थी इसलिये मैंने उसका क्लैरीफिकेशन किया। आपने अभी कोई सवाल नहीं किया।

In reply to the main Question, I say that a statement is laid on the Table of the Sabha.

PROF. MADHU DANDAVATE : The guard went first and the driver came afterwards !

Procurement Price of Wheat

\+

*104 SHRI SURAJ BHAN :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the comments received on the recommendations made in the Agricultural Prices Commission's report on Price Policy for wheat for 1981-82 crop (to be marketed in 1982-83) from wheat producing and consuming States ;

(b) decision taken in this regard ; and

(c) recommendations of the Agricultural Prices Commission which have not been accepted and reasons therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The Report of the Agricultural Prices Commission on Price Policy for Wheat for 1981-82 crop was sent to the Governments of twelve important wheat producing and consuming States, namaly, Assam, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. All the States except Maharashtra hava sent their replies. Tamil Nadu has stated that they have no comments to offer. The procurement price suggested by other States are as under :

States	Procurement price suggested
	(Rs. per quintal)
Assam, Karnataka & Jammu & Kashmir	142
Bihar, Rajasthan and West Bengal	150
Haryana	160
Punjab	161
Uttar Pradesh	164
Madhya Pradesh	175

(b) The question of fixation of procurement price of wheat for 1982-83 marketing season is under the active consideration of the Government.

(c) Other recommendations of the Agricultural Prices Commission relate to varietal diversification in the matter of research and development of wheat and keeping the prices of agricultural inputs under control. The Government policies on research and development of wheat and prices of agricultural inputs are already directed to the achievement of these objectives.

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सरकार के अपने बयान के मुताबिक देश में बहुत गेहूं पैदा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी बाहर से गेहूँ मंगवाना पड़ा क्योंकि किसान को ठीक दाम नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते इत्तफाक से आपके फार्म की चर्चा थोड़ी सी हुई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके फार्म पर एक टन गेहूं पैदा करने में कितना खर्चा होता है मेहरबानी करके यह मंत्री

महोदय को आप बता दें। उसको ध्यान में रखते हुए और ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज जो देश में हैं उनका क्या खर्चा पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर····

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, यह आप से पूछ रहे हैं या मंत्री जी से पूछ रहे हैं ?

श्री सूरज भान : गेहूं की कीमत तय करें। किसान का खर्चा तो है ही, उसे कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा भी चाहिए इस बात को भी ध्यान में रखें। बाहर से आपको गेहूं मंगाने पर 200 रु० प्रति क्विंटल से ज्यादा देना पड़ता है। तो आप किसान को कितना देना चाहेंगे इस बात की घोषणा गेहूं बोने से पहले कर देनी चाहिये। क्या आइन्दा आप ऐसा करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान के पैदावार करने में क्या-क्या खर्चा होता है और जितनी चीजें होती हैं, सबका हम अन्दाजा लगाकर साइंटिफिक बेसिस पर, यूनिवर्सिटीज से पूछकर, हमारी अपनी आर्गेनाइजेशन्स हैं जिनके जरिये हम फार्म लेवल तक पता करते हैं कि क्या-क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन है और वह डिफरेंट स्टेट्स में अलग-अलग होती है, यहां तक कि खेत-खेत में भी फर्क होता है. एक किसान और दूसरे किसान की जमीन में बराबर-बराबर खेत हों तो उसमें भी फर्क होता है।

एक माननीय सदस्य : एवरेज लीजिये।

राव वीरेन्द्र सिंह : एवरेज ली जाती है, लेकिन जब कास्ट आफ प्रोडक्शन ली जाती है तो उसमें जो किसान खर्च करता है उसका सूद, जहां से कैपिटल लेता है उसका हिसाब, जमीन उसकी अपनी है या उसने ठेके पर, किराये पर ली हुई है उसका भी हिसाब लगाया जाता है, जितने इनपुट्स वह इस्तेमाल करता है, उनकी उस वक्त क्या कीमत है जब कि वह पैदावार कर रहा है, और अब तो हमने यह भी कर दिया है कि ट्रांस्पोर्ट का खर्चा भी जो किसान का खेत से मंडी तक या फैक्टरी तक ले जाने में होता है, वह भी कास्ट आफ प्रोडक्शन में शामिल किया जाता है, उसकी अपनी और फैमिली की जो मेहनत होती है, उनकी वेजेज भी उसमें शुमार होती हैं। इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है और उसके बाद यह कास्ट आफ प्रोडक्शन कैल्कुलेट होती है जिसमें प्राफिट का मार्जिन भी शामिल होता है।

यही नहीं, ज्यों ही यह सरकार बनी, हमने पहला फैसला यह किया था कि दूसरी चीजों के दाम, जो एग्रीकल्चर के सैक्टर में पैदा नहीं होती हैं, उनके दाम जिस हिसाब से बढ़ते रहते हैं, उनके साथ पैरिटी रखने की कोशिश की जायेगी। किसान की पैदावार का दाम उतना नीचे नहीं रहने दिया जायेगा कि दूसरी चीजों के मुकाबले में उसको नुक्सान हो अपनी पैदाबार पर। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर सपोर्ट प्राइस तय की जाती है। इसमें बहुत से फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि सूरजभान जी भी किसान के हक में बोल रहे हैं आज।

श्री सूरज भान : इस स्टेटमैंट में 6 स्टेट्स की तरफ से जो रिकमैंडेशन्ज आई हैं, उनमें से 4 ने लिखा है कि 160 से ऊपर होना चाहिये। हरियाणा ने 160 लिखा है, पंजाब ने 161 लिखा है, उत्तरप्रदेश ने

164 और मध्यप्रदेश ने 175 लिखा है। मंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं बताया कि कितना करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा आपने कहा, क्या इनपुट्स के लिए आप एरेन्जमैंट करेंगे ? जनता रिजीम में खाद के एक बोरे की कीमत 100 से घटाकर 72 कर दी गई थी, अब 119 हो गई है। क्या आप इस किस्म के स्टैप्स उठायेंगे ? अगर आप गेहूं की प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते तो इनपुट्स के दाम घटा दीजिये, लेकिन आपके जवाब से बड़ी मायूसी हुई है जब आपने कहा कि गेहूं की कीमत 142 रुपये से भी घट सकती है। कम से-कम कुछ तो अन्दाज़ा दीजिये कि आप क्या करना चाहते हैं जिससे किसान को राहत मिले और आपको फिर दूसरे मुल्कों के सामने भीख का कटोरा लेकर न जाना पड़े ?

राव बीरेन्द्र सिंह : याद तो मुझे सब कुछ है, लेकिन जो मैंने कहा है वह हकीकत है।

जब ए० पी० सी० की रिपोर्ट सरकार सामने रखकर गौर करती है तो यह जरूरी नहीं कि ए० पी० सी० की रिकमेंडेशन्स को मंजूर कर लिया जाये, क्योंकि पिछली बार ए० पी० सी० ने जो सिफारिश की थी, तो उससे भी ऊपर दाम तय किये थे। अगर ऊपर दाम तय कर सकते हैं तो ए० पी० सी० की रिपोर्ट से नीचे भी दाम तय कर सकते हैं। यह इसलिये कि वह एक एडवाइज़री बाडी है और अगर सिर्फ उसी की रिपोर्ट पर चलना हो तो फिर आपकी राय का तो हम फायदा उठा ही नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : सूरजभान जी की राय का फायदा उठा लीजिये। **(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह : नाउम्मीद न हों, आप उम्मीद रखिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हम लोगों की राय से फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिये मैं अपनी राय दे रहा हूं। किसान की मदद करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और जो नान-एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतों में पैरिटी कायम कर दीजिये और दूसरा तरीका यह है कि इनपुट्स की कीमत और आउट-पुट्स की कीमत में कोई लिंक होना चाहिये। अभी तक दोनों काम नहीं हुए हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन फसल के दाम तय करता है, लेकिन फर्टिलाइज़र, डीज़ल, इक्विप्मेंट, मशीनरी, इनके दाम तय करना एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के जिम्मे नहीं है, क्या इन चीजों का दाम तय करने का भार भी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को सौंपा जायेगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या श्री वाजपेयी चाहते हैं कि ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मंत्री महोदय ने हमारी बात सुनी नहीं है, तो वह उससे फायदा कैसे उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा है कि ट्रैक्टर्ज और इम्प्लीमेंट्स वगैरह के दाम तय करने के लिए भी कोई कमीशन होना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री वाजपेयी का मतलब मैं यह समझा हूं अपनी छोटी अक्ल से कि चूंकि सरकार पैरिटी मेनटेन करना चाहती है, इस लिए जितनी चीजें फैक्टरियों में बनती हैं और किसानों के काम में आती हैं, जितने कनज्यूमर गुड्ज हैं, उनके दाम तय करने का काम भी ए पी सी को सौंप दिया जाए।

MR. SPEAKER : I think we can have a discussion on this sometime.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : May I put the question in English ? राव साहब को हिन्दी समझने में कुछ मुश्किल हो रही है ।

Sir, there is no parity in the prices of agricultural commodities and non-agricultural commodities at the moment. Nor is there any linkage between the prices of inputs and prices of outputs. I would like to know whether the Agricultural Prices Commission will be entrusted with the task of fixing the prices of agricultural inputs, namely, fertilisers, diesel, equipment and machinery ?

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, it is absolutely impossible to entrust the APC with the responsibility of fixing prices for such a large number of inputs that are used in agriculture, namely, fertilisers which are produced in factories and also imported from outside; for water rates which the Government charges on canal water and on State tublewells ; for electricity for which there is a separate Department. They have to look into their own economics. Similarly there are so many other things. The Bureau of Industrial Costs and Prices comes in for fixing prices but where the question of inputs used by the farmer comes in we try to take the current prices into account while fixing the prices. We have said that we compensate the farmer for higher prices which prevail at a particular time when APC sends its recommendations and Government can take into account later if there is rise in prices at a time when decision is taken.

I knew what Vajpayee meant but I was trying to explain the difficulties which will come in the way because the question of parity is relevant not only for inputs that the farmer uses but also in respect of goods produced in the non-agricultural sector, that is, consumer goods also. But can one body be entrusted with all that ? It is impossible. Sir inadvertantly I committed an error when earlier I stated that the production of foodgrains this year is expected at 130 million tonnes. We expect it at 134 million tonnes which is 2 million tonnes higher than the previous record of 132 million tonnes.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Sir, the Hon. Minister was saying that the inputs prices are taken into consideration when they fix up the prices. I would like to know whether the Hon. Minister is aware of the fact that last year the price of urea per bag was Rs. 74 and this year it is Rs. 125 per bag. Last year the price of DAP per bag was Rs. 175 and this year it is Rs. 225 per bag. There are also other things which the farmer is compelled to purchase and they do not get at the fixed rate, namely, cement for which the controlled price is Rs. 35 per bag he has to purchase at Rs. 85 per bag in the black-market. So is the question of steel and other things. So is the question of kerosine oil and so many other things. The main things where the farmers feel really very acutely and strongly are these. In respect of whatever they have to purchase from the market in regard to industrial goods, their prices are very high and while they produce more, they do not get a reasonable price. I would like to know from the Minister whether it has come to his notice that the Agricultural Prices Commission's recommendations have always been impracticable and many times Government had to change the main recommendations of the Agricultural Prices Commission. So, will the

Government take into consideration the suggestion made that the Agricultural Prices Commission should be abolished and Government instead should appoint a National Price Commission which should be able to go into fixation of price of industrial goods as well as the agricultural goods, so that a kind of parity is made to prevail, and farmers are not discriminated against so far as granting of reasonable price to his produce is concerned ? Then, the last part of my question is this.

MR. SPEAKER : It has already taken too long.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Last part of my question is this :

Taking into consideration all the above circumstances, will the Minister ensure that farmers are enabled to get the essential goods of their utility, of their use, by the public distribution system, so that these things are also made available to them at fixed prices, things like cement, kerosine oil, petrol, sugar, etc.?

RAO BIRENDRA SINGH : In our scheme of Public Distribution System most of the essential commodities are covered—things like cement, kerosine oil, fertilisers etc. Fertiliser is also controlled and the distribution is done through Government agencies, cooperatives, etc. Most of the other important inputs like irrigation, power etc. are also brought under Government's control. The main question by the Hon. Member Shri Chandrajit Yadav was in the form of a suggestion.

PROF. N. G. RANGA : An excellent suggestion.

RAO BIRENDRA SINGH : It was a very big question and I cannot react to it immediately. But Government have noted this suggestion—whether there can be some way of having some mechanism for the fixation of prices all over in all sectors.

MR. SPEAKER : Industrial prices jump up like anything.

RAO BIRENDRA SINGH : I am aware that we had to increase fertiliser price in the past on one or two occasions. I also admit that the consumption of fertiliser on account of that has gone down to some extent. But then Government is also conscious of this situation. It is because of this that recently it has been announced by the Finance Minister that there will be concessions given on import of some fertilisers like Calcium Ammonium Nitrate. That is part of our policy to bring down the fertiliser price to the extent possible. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : It has already taken 25 minutes.

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : स्पीकर साहब, सही बात यह है कि कीमत मुकर्रर करते वक्त अभी तक सरकार इन्साफ नहीं करती रही है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया, जो भी किसान की जरूरियात की चीजें हैं उनकी कीमत को ध्यान में रखकर कीमत मुकर्रर की जाती है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो कीमतें वे ध्यान में रखते हैं उसमें क्या किसान जो अपने खेत में मेहनत करता है, खेत में वह जो खुद, उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसका सारा कुनबा लगा रहता है···

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया है।

AN HON. MEMBER : Let us have a special discussion.

MR. SPEAKER : That is what I suggested.

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कैसे इस बात

का अन्दाजा लगाते हैं कि एक खानदान के कितने व्यक्ति एक खेत में काम करते हैं ? किसी के पांच लड़के काम करते हैं, किसी के तीन लड़के काम करते हैं, उसकी औरत काम करती हैं तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आप पर क्विंटल क्या मुनाफा देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुशीर साहब, यह तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : सारी कीमतें लगाने के बाद आप पर-क्विंटल किसान को क्या मुनाफा देते हैं—यह मैं जानना चाहता हूं ।

MR. SPEAKER : Has the Hon. Minister got anything to add ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने जवाब दिया है कि सारी मेहनत, उसकी फैमिली और मजदूर जितने काम करते हैं, उसमें शामिल होगी । अगर कोई खास रिश्तेदार आप गिनवाना चाहते हैं, तो मैं उसकी लिस्ट बनाकर भेज दूंगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष जी, यह कोई जवाब नहीं है । इरिसपांसिबल जवाब है । मैंने आपसे पूछा है कि आप मार्जिन आफ प्राफिट पर-क्विंटल के हिसाब से किसान को क्या देना चाहते हैं ?

MR. SPEAKER : Next question—105. Mr. Amar Roy Pradhan.

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया । 25 मिनट तो इसी सवाल पर हो गए हैं । इस पर डिसकशन करवा देंगे, यह बहुत लम्बा विषय है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मार्जिन आफ प्राफिट के बारे में पूछना है । फेयर मार्जिन आफ प्राफिट देकर सरकार कीमत तय करती है । मार्जिन आफ प्राफिट हर किसान के लिए अलग मुकर्रर नहीं की जाती है । हर एक किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन अलग है । मार्जिन आफ प्राफिट पर-क्विंटल की बात करेंगे तो हमें एक-एक किसान के एक-एक खेत पर जो कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है, उसको देखना पड़ेगा । इट-इज़-इम्पोसिबल ।

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा था और राव बीरेन्द्र जी को याद करवाना चाह रहा था, जब वे हरियाणा में मुख्य मंत्री थे, जौ और मक्के की बाबत कहा करते थे कि लिफाफों में बिकवा देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि 104 रु० क्विंटल के हिसाब से खाद का भाव बढ़ गया, लेकिन गेहूं का भाव 13 रु० से ज्यादा नहीं बढ़ा सके । उन्होंने कहा है कि प्राइस-कमीशन एक एडवाइज़री बाडी है । आज तो आप मालिक हैं, थोड़ी हिम्मत कर दीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन्स हैं, वे तो आपकी है, उसे तो पूरा कर दीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहब, आपको याद नहीं है, कीमत इनके वक्त में मुकर्रर हुई थी 115 रु० । उसके बाद दो बरस में 15 रु० बढ़ा दी है, गेहूं की कीमत ।

श्री देवी लाल : खाद का भाव 104 रु० क्विंटल कर दिया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : गेहूं की कीमत दो बरस में 130 रु० कर दी है ।

श्री देवी लाल : कपास के भाव की वजह से कपड़े का भाव बढ़ रहा है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : कपास का भाव आपके समय में 208 रु० था । अब 500-550 रु० दे रहे हैं । स्पीकर साहब जानते हैं ।